

रकूल शिक्षा विभाग ने डीईओ को दिए निर्देश, काउंसलिंग से चुन सकेंगे रकूल जीरो एडमिशन वाले रकूल के टीचर्स के होंगे तबादले

दोपहर मेट्रो, भोपाल।

प्रदेश के जिन विद्यालयों में चालू शिक्षा सत्र में एक भी विद्यार्थी का एडमिशन नहीं हुआ है, ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को अब उन विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा जहां टीचर्स की कमी है। इसके लिए रकूल शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग के जरिए ऐसे टीचर्स को शाला विकल्प चुनने का मोका देने का फैसला लिया है।

काउंसलिंग की कार्यवाही 12 सितंबर को की जाएगी। इसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ताकीद किया है कि जो भी कार्यवाही की जाए अगर पूरी पारदर्शिता और सुचिता के साथ होनी

चाहिए। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज जानकारी के अनुसार जिलों में शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों को उन विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। इसी तारतम्य में शून्य नामांकन (नो न्यू एडमिशन) वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों की जानकारी गूगल शीट जरीए एनरोलमेंट स्कूल टीचर डेटा फॉर्म काउंसलिंग पर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को शेयर की गई है। इसके अलावा अगर किसी स्कूल के शिक्षक छुट्टे हों तो उनकी एंट्री गूगल शीट पर की जाना हो।

कल दोपहर होगी काउंसलिंग



पहले दिया जाएगा। काउंसलिंग में मौजूद शिक्षकों द्वारा चयन किए गए विकल्प का सहमति पत्र लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर शाला विकल्प का चयन करना है। ऐसे शिक्षक जो काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होंगे या शाला विकल्प चयन नहीं करेंगे। उनकी पदस्थापना जिले में किसी भी रकूल में की जा सकेगी।

जिला स्तर पर काउंसलिंग सीनियराईटी के आधार पर की जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ग्रेजेशन लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग करेंगे यानी सीनियर टीचर की शाला विकल्प का मोका

मध्यप्रदेश को मिला 'बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड' अवॉर्ड केंद्रीय मंत्री शशावत ने प्रदान किया अवार्ड

भोपाल। केंद्रीय पर्टन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शशावत ने मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को प्रतिष्ठित बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया है। यह सम्मान नई दिल्ली के लौ मेरिडियन में भव्य ईंडिया ट्रैल अवॉर्ड्स 2025 समारोह में प्रदान किया गया। इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मान ने भारत के पर्यटन क्षेत्र में नवाचार, उत्कृष्टता और सतत विकास को लेकर मध्यप्रदेश की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया है। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्वर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रधार) धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि यह सम्मान मध्यप्रदेश की जनता और यहां की संस्कृति के गौरव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन को विकास की धूमी बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश की धरोहर, प्राकृतिक संपदा और लोक-पांपांगों को विश्वस्तर पर प्रचान दिलाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यह अवॉर्ड हमें और ऊर्जा देता है कि हम पर्यटन को न केवल राज्य की पहचान, बल्कि रोज़गार और आत्मनिर्भरता का मज़बूत साधन भी बनाएं।

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन करें आवेदन

बिजली के धारा 126 के मामलों में छूट का मौका

भोपाल। म.प्र. मध्य शेत्र विवृत वितरण कंपनी के कायदे शेत्र के भोपाल, नवमदापुरम, खालियर एवं चौबल संघाय के 16 जिलों के उपभोक्ताओं के लिए धारा 126 में लैबिट प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदन 01 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता कंपनी पोर्टल पर जाकर प्रदर्शित क्लीक लैब में Rebate As lokadalat in section 126 पर विलक्ष कर आवेदन प्रस्तुत करना होता। कंपनी के portal.mpcp.in पोर्टल पर कंज्मर एडीडी की प्रविष्टि करते ही कोड धारा-126 में दर्ज लैबिट प्रकरण प्रदर्शित होगा। उपभोक्ता को लोक अदालत की तर्ज पर धारा-126 में छूट प्राप्त किए जाने हेतु -उपभोक्ता के परिसर या अन्य परिसर पर संयोजन के विस्तृद्ध विवृत देयक की बकाया राशि नहीं है बला विचाराधीन प्रकरण पर धारा 127 के अंतर्गत गवाई अपीलीय प्राधिकरण के समझ या किसी अन्य न्यायालय के समझ कोई अपील लैबिट नहीं है न ही निनिंग है। स्थायित कर सभीट करना होगा। इसके बाद उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चयन कर भुगतान कर सकते हैं। इसके प्रकार ऑफलाइन आवेदन हेतु उपभोक्ताओं के लिए नन्दीकी विवृत वितरण केन्द्र/जोन पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

लोक अदालत की तर्ज पर मिलेगी छूट

कंपनी ने कहा है कि विवृत अधीनियम 2003 की धारा 126 के लैबिट प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माह के दौरान ही किया जाएगा। लोक अदालत की प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित मापदंडों के अधीन 10 लाख रुपए तक की सिविल दायेत की राशि के समत घरेलू समसर का, 5 किलोवट तक गैर घरेलू व 10 अश्वकि तक के औद्योगिक श्रेणी के लैबिट प्रकरणों का आवेदन संबंधित उप महा प्रबंधक की दिया जाकर, आकित राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकित राशि के भुगतान में दूर किए जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने की तीव्र से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने पश्चात प्रत्येक 6 माही बढ़कर्ता दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लाने वाले व्याज की राशि पर, 100 फीसदी की छूट दी जाएगी।

भोपाल में मछली कनेक्शन की कान्हासैया और अनंतपुरा में जांच

66 साल पुराना रिकॉर्ड खंगाल रहा अमला

दोपहर मेट्रो, भोपाल।

भोपाल में एक और कॉलोनी में मछली कनेक्शन की पड़ताल शुरू हो गई है। कान्हासैया और अनंतपुरा के 57 खसरों की जांच की जा रही है तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी वर्ष 1959 यानी 66 साल पुराने रिकॉर्ड को भी खंगाल रहे हैं।

हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि 10 दिन में विस्तृत रिपोर्ट देने की कहाँ है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अनंतपुरा और कान्हासैया की आनंद लेकर सिटी कॉलोनी को लेकर एसडीएम सोनकिया को शिकायत की गई थी। इसमें बताया गया कि कॉलोनी में एक रिकॉर्ड खंगाल का अन्तर्गत एक खसरों को खसरे नंबर-18 एकड़ में कॉलोनी डेवलप कर 170 से ज्यादा प्लॉट बेचे गए हैं। कॉलोनी में सीसी रोड भी बनाई गई है। वहाँ, एक ही



समुदाय को प्लॉट बेचे गए हैं। कॉलोनी डैम से सटे खसरे नंबर 31 से 47 तक बनी हैं। यह जमीन 1959 से सिन्चाई विभाग के सरकारी खसरों में दर्ज है। करीब 18 एकड़ में कॉलोनी डेवलप कर 170 से ज्यादा प्लॉट बेचे गए हैं।

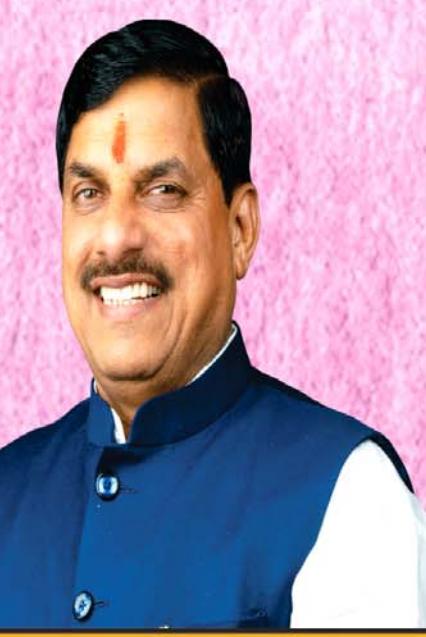
इन खसरों की जांच

अनंतपुरा के खसरा नंबर- 79, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101 और 102। ये खसरे साल 1959 में शासकीय भूमि में दर्ज होना सामने आया है। अनंतपुरा में ही खसरा नंबर- 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 98, 99, 100, 103, 104, 105 और पूर्व के खसरे नंबर-635/498, 533, 534, 535, 536, 537/2/2, 537/2/1, 537/1, 639/539, 639/539/2 का साल 1959 से लेकर वर्तमान तक की स्थिति में जांच कराई जा रही है। यहीं पर कॉलोनी का निर्माण सामने आया है। कानासैया गांव के पूर्व के खसरा नंबर- 111, 445, 512, 593/3, 596, 690/1, 691, 692, 696, 679/1, 698 और वर्तमान के खसरे नंबर-728, 864, 569, 582, 535, 530, 190 की साल 1959 से लेकर वर्तमान तक की स्थिति की जांच की मांग की गई है।



उज्ज्वल भविष्य की बुनियाद गढ़ती शिक्षा

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

7832 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण

सेनिटेशन एवं हाइजनीन हेतु 20 लाख से अधिक बालिकाओं को ₹61 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण



11 सितंबर 2025 | पूर्वाह्न 11:00 बजे

कुशामाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार, भोपाल

वर्ष 2022 से संचालित योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पेट्रोल स्कूटी के लिए ₹ 90 हजार तथा ई-स्कूटी के लिए ₹ 1.20 लाख की राशि प्रदान की जाती है।

अं तरारस्थीय राजनीति भी अब बॉनीवडुड की मसाला फिल्मों जैसी हो चली है। वहाँ भी नायक मुस्कुराकर गले लगता है, और अगले ही पाल पीठ में छुरा घोंप देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रॉप इस कला में महिर निकले। साथल मीडिया पर बार-बार प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी को 'माय गुड फ्रेंड' बताने वाले ट्रंप, असल में भारत की जेब पर 100 प्रतिशत टैरिफ का वार करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्ती की मिठास के पीछे छिपा यह कड़वा सच बताता है कि वैश्विक राजनीति में आई लव

यू.बट... वाली रणीति खुब चलती है। ट्रंप का तर्क बड़ा सीधा है—जब तक भारत और चीन करते हैं। तब तक दोनों पर 100 प्रतिशत टैरिफ थोप दो। मतलब साफ है—'तेल नहरें छोड़ें, तो व्यापार निचोड़ देंगे'। दिलचस्प बात यह है कि चीन रूस संस्कृत ज्यादा तेल खरीदता है, लेकिन टैरिफ का डंडा भारत पर ज्यादा कसकर बरस रहा है। चीन पर जहाँ 30 प्रतिशत टैक्स है, भारत पर पहले ही 50 प्रतिशत तक का बोझ

दोस्ती के नाम पर छुरा

लादा जा चुका है। यानी दोस्त पर सख्ती और प्रतिद्वंद्वी पर नसी—इसे कहते हैं कूट्टनीति की 'ट्रॉफ़िक'। कुछ दिनों पहले ही भारत, चीन और रूस के नेताओं की एससीओ शिखर सम्मेलन में मूलाकात हुई। तस्वीरें देखकर ट्रंप को शयद ऐसा लगा कि यह दोस्ती की फोटो नहीं बल्कि साजिश की फोटो है। उन्होंने इष्पणी भी कर

टैरिफ की धमकी। लेकिन हफ्ते भर बाद वही ट्रॉटिवर पर लिखते हैं—'मोदी माय गुड फ्रेंड'। यह वैसा ही है जैसे कोई आपके घर का दरवाजा तोड़कर बुस आए और पिर बोले—'भाई, कॉफी पिला दो।' यह पूरी कहानी हमें एक पुराना मुहावरा याद दिलाती है—'दुश्मन से सावधान रहना आसान है, मुश्किल तो तब होती है जब

दोस्त ही छुरा घोंपे।' अमेरिका की दोस्ती पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे बिच्छु से उमीद करना कि वह डंक नहीं मारेगा। भारत को अब यह समझ लेना चाहिए कि वाईशंगटन की मुख्याने असल में व्यापारिक कैलंकलेटर हैं। अज दोस्ती की बातें, कल टैरिफ का मार-यही असली अमेरिकी समीक्षण है। इसलिए भारत के लिए बेहतर यही होगा कि वह अपने रिश्तों की गाड़ी सिर्प एक पटरियों पर न दौड़ाए। क्योंकि अगर अमेरिका जैसा दोस्त हो, तो दुश्मनों की जरूरत ही क्या है?

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को क्यों नहीं पूरा होने देना चाहती कांग्रेस?

■ डॉ. मयंक चतुर्वेदी

भा

रतीय लोकतंत्र का सबसे दिलचस्प पहल यह है कि यहाँ रास्थीय महत्व की किसी भी योजना पर राजनीतिक बहस इतनी तेज हो जाती है कि असली तथ्य पीछे छुरा जाते हैं और जनता के समाने आधे-अधूरे सच पहुंचते हैं। ग्रेट निकोबार की सम्प्रविकास परियोजना इसका ताजा उदाहरण है। यह परियोजना केवल एक बंदरगाह या हवाई अड्डा नहीं है, इससे बहुत अगे भारत की समुद्री सुक्ष्मा, वैश्विक व्यापार में भागीदारी और ट्रेड-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति सुतुलन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। किंतु इसे लेकर कांग्रेस बार-बार शक्ति और धर्म का वातावरण बनाया जाना को यह जानने की कोशिश करता है कि मानों सकारा देश और समाज को किसी बड़े संकर की ओर धकेल रही है।

केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत की सुरक्षा के एक मजबूत किले के रूप में विकसित करने का सकल्प लिया है। ऐसा व्यापक है कि इस दिशा में ग्रेट निकोबार परियोजना एक 'गेमचेंजर' साबित हो सकती है। इसके अंतर्गत गैलेगिया खाड़ी में विश्वस्तरीय अंतर्रास्थीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफोल्ड अंतर्रास्थीय हवाई अड्डा, 300,000 से 400,000 लोगों के लिए एक नियोजित टाइनशिप, 450 एमवीए क्षमता वाला गैस और सौर आधारित पॉवर प्लॉट और सड़कों-जलगृहों का नेटवर्क तैयार किया जाना है। नीति आयोग के नेतृत्व में और एनआईआईडीसीओ के माध्यम से चल रही इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 81,000 करोड़ रुपये है।

आज राजनीतिक दृष्टि से ग्रेट निकोबार का महत्व किसी से छिपा नहीं है। यह मलकार ताजलमस्तुत्य के पश्चिमी छोर और सिक्स डिग्री चैनल के पास स्थित है। दुनिया के 30 से 40 प्रतिशत समुद्री व्यापार जहाँ इसी रासे से जुराते हैं और चीन की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा भी यही से आती है। यदि भारत इस क्षेत्र में मजबूत उपरिस्थिति दर्ज करता है तो दिव्य महासागर में बीजिंग की विस्तारादाई 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' आपूर्ति को सीधी चुनौती मिलेगी। एक ओर चीन व्यापार, हवाई सेवा और बड़े बंदरगाहों में निवेश करके हिंद महासागर में धोरावंडी कर रहा है, तो दूसरी ओर भारत का यह कदम स्वाभाविक रक्षा प्रतिक्रिया है। जोकि पूरे हिंद-प्रशांत की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नैसैनिक दृष्टि से भी यह योजना दूरगमी है। प्रस्तावित हवाई अड्डा नागरिक और सैन्य, दोनों उपयोग के लिए होगा। यह भारत की एकमात्र विस्तृत कामना और निकोबार कमान को तकाल कैनाती और निगरानी की नई क्षमता देगा। नैसैनिक योजना के युद्धोपयोग, एयर फोर्स के विमान और शरस्वती से तेजी से संचालित की जा सकेगी। यह केवल रक्षा और व्यापार नहीं, बल्कि मानवीय सहायता और आपातकालीन रक्षा की भी केंद्र बनेगा।

वस्तुतः अधिक दृष्टि से यह परियोजना भारत के लिए बदलन है। आज भारत के केंटर जहाजों को सिंगापुर या कोलंबो को समाप्त कर दिया और इसके लिए एक अंडमान और निकोबार कमान को तकाल कैनाती और निगरानी की नई क्षमता देगा। इसकी अभाव पहले चरण में 4 मिलियन टीटैंड होगी और 2050 तक यह 16 मिलियन टीटैंड तक पहुंच सकती है। यह भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाएगा, विदेशी मुद्रा की बचत करेगा और हजारों करोड़ रुपय का अतिरिक्त

राजस्व उत्पन्न करेगा। इसके साथ ही इस परियोजना से लगभग ढाई लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। पर्यावरण, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा और स्वास्थ्य के नए अवसर खुलेंगे। लेकिन कांग्रेस इस योजना को 'दुस्साहस-बताकर आदिवासी अधिकारों और पर्यावरणीय खतरे का मुद्दा उठ रहे हैं।

सोनिया गांधी में हाल ही में एक लेख में वेतावनी दी कि यह परियोजना शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के अस्तित्व के लिए सकट है और इससे लाखों पेड़ काटे जाएंगे। जयप्रकाश रमेश ने पेड़ों की संख्या 8.5 लाख से बढ़ाकर 32 से 58 लाख तक बढ़ाई और इसे पर्यावरणीय विनाश कहा। राहुल गांधी ने जनजातीय मालों के मत्री को पत्र लिखकर बन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन की बात उठाई। इन आरोपों में सच्चाई कितनी है, यह

आदिवासी अस्तित्व पर हमला बनाना क्या दोहरा रखेया नहीं है? आज आईएनएस बाज भारतीय नैसैनिक हवाई स्टेशन है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंपबेल बे से भारत के दक्षिणी क्षेत्र की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मलवका जलडमरम्याद और सिक्स डिग्री चैनल पर नजर रखने में मदद करता है। क्या कोई इस समारिक महत्व को नकार सकता है? परियोजना के विरोध में भूकपीय जीवित का तर्क भी दिया जा रहा है। 2004 की सुनामी के समय यह क्षेत्र प्रभावित हुआ था, लेकिन उसके बाद से ही यहाँ गांधी ने जनजातीय मालों के मत्री को पत्र लिखकर बन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन की बात उठाई। यह से भेद नहीं कि यह आपातकालीन विवाह विनाश करता है।

बसाया जाए। इस दृष्टि से देखें तो भारत के उल्लंघन जीवित माल वाले भूकपीय क्षेत्रों में उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालयी क्षेत्र (जैसे कश्मीरी और उत्तर बिहार), युगरात का कञ्चल क्षेत्र और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं, जहाँ शवित्रशाली भूकपीय अस्तकरण होता है। इन क्षेत्रों में दिल्ली, श्रीनगर और गुवाहाटी जैसे कई बड़े शहर भी स्थित हैं जो भूकपीय के प्रति संवेदनशील माने जाते हैं। तब तो फिर इस समीक्षण के बारे में जायेगा। कांग्रेस ही यहाँ से भूकपीय क्षेत्रों में एक लोकतांत्रिक विवाह विनाश करता है।

सबात यह है कि यह साथ से भूकपीय क्षेत्रों में उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालयी क्षेत्र (जैसे कश्मीरी और उत्तर बिहार), युगरात का कञ्चल क्षेत्र और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं, जहाँ शवित्रशाली भूकपीय अस्तकरण होता है। इन क्षेत्रों में दिल्ली, श्रीनगर और गुवाहाटी जैसे कई बड़े शहर भी स्थित हैं जो भूकपीय के प्रति संवेदनशील माने जाते हैं। तब तो फिर इस समीक्षण की बारी दूर होती है। यहाँ से भूकपीय क्षेत्रों में एक लोकतांत्रिक विवाह विनाश करता है।

बसाया जाए। इस दृष्टि से देखें तो भारत के उल्लंघन का रास्तीय दियत्व है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में कहा कि यह परियोजना का मंजुरी दी गई है। यह क्षेत्रों के विवाह विनाश करता है। जैसे कीद्री मत्रियों ने बार-बार स्पष्ट किया है कि यह योजना के बारे में भूकपीय क्षेत्रों के विवाह विनाश करता है।

वास्तव में यदि विषय यदि इस पर हमें अपने सामरिक हिंदू देखने तो भारत के आधार के उल्लंघन की बात आदिवासी अधिकारों की अधिकार विवाह विनाश करता है। जैसे भूकपीय क्षेत्रों में उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालयी क्षेत्र (जैसे कश्मीरी और उत्तर बिहार), युगरात का कञ्चल क्षेत्र और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं, जहाँ शवित्रशाली भूकपीय अस्तकरण होता है। इन क्षेत्रों में दिल्ली, श्रीनगर और गुवाहाटी जैसे कई बड़े शहर भी स्थित हैं जो भूकपीय के प्रति संवेदनशील माने जाते हैं। तब तो फ

સ્વાસ્થ્ય કર્મચારી સંઘ કે બૈનર તલે બડી સંખ્યા મંનું કર્મચારિયોંને કી નારેબાજી ઈ-અટેક્સ સે વેતન રોકને કા વિરોધ, કહા-ગ્રામીણ થોત્રો મંનું નહીં મિલતે મોબાઇલ નેટવર્ક

મનોજ ગૌડ, ખરગૌન

પ્રદેશ મંનું સાર્થક એપ કે માધ્યમ સે ઈ-અટેક્સ (હાજરી) કી અનિવાર્ય વ્યવસ્થા લાગુ કરને કે બાદ કર્મચારીયોંનું ગુસ્સા થતું કી નામ નહીં લે રહ્યા હોય। ઇસ વ્યવસ્થા કો કોષાળય પ્રાણીસે જોડતે હુએ વેતન ભૂગતાન આધાર બના દિયા ગયા હૈ। બૃહુત્સેધ્યે સ્વાસ્થ્ય કર્મચારી સંઘ કે બૈનર તલે બડી સંખ્યા મંનું કર્મચારી સીએમેચોઓ કાર્યાલય પરિસર પહુંચે ઔર જમકર નારેબાજી કરતે હુએ ઇસ નિર્ણય કી વિરોધ કર્યા।

કર્મચારીયોંને કહા કી ખરાગોન સહિત પ્રદેશ કે કઈ જિલે આદિવાસી બાહુદ્ય ઔર દૂરસ્થ ગ્રામીણ થોત્રોને આતે હોય। યાં આજ ભી સર્કરોની કી સ્થિતિ ખરાબ હૈ ઔર મોબાઇલ નેટવર્ક કી સુવિધા બેદદ સીમિત હૈ। એસે ઇલાકોને પદસ્થ કર્મચારીયોંની કી ખરાગોન સહિત પ્રદેશ કે કિંમત દર્જ કરાના અસ્થિર હૈ। ઉછોનેને સવાલ ઉદાય કી યદિ નેટવર્ક નહીં મિલતું યા સર્વર ડાઉન હુએ તો ક્યા હાજરી હાયા? ઇસે કર્મચારીયોંને સીધી અન્યાન્ય બતાયા। સંઘ પદાધિકારીયોંને કી શાસન ને હોય વ્યવસ્થા બિના ઠોસ તોયારી ઔર પરિશીખ કે લાગુ કી હૈ। હાલે ઈસે કુછ જિલોને પાયાલટ પ્રોજેક્ટ કે રૂપ મંનું લાગુ કીયા જાતું ઔર ખામીઓની કો દૂર કિયા જાતું અને પાયાલટ કે રૂપ મંનું લાગુ કીયા જાતું, લોકિન જલદ્બાજી મંનું પૂરે પ્રદેશ મંનું



કર્મચારિયોંની આપત્તિયાં

- ગ્રામીણ ઔર પહાડી ઇલાકોને નેટવર્ક સમયાં કી દર્જ કરાના કારણ હાજરી ને સીધી અન્યાન્ય બતાયા। સંઘ પદાધિકારીયોંને કી શાસન ને હોય વ્યવસ્થા બિના ઠોસ તોયારી ઔર પરિશીખ કે લાગુ કી હૈ। હાલે ઈસે કુછ જિલોને પાયાલટ પ્રોજેક્ટ કે રૂપ મંનું લાગુ કીયા જાતું ઔર ખામીઓની કો દૂર કરાયા જાતું।
- તકનીકી ગડવદી યા સર્વર ફેલ કા નુકસાન કર્મચારિયોંની તુઠાન પડ્યા।

લાગુ કર દિયા ગયા કર્મચારીયોંને સ્પષ્ટ ચેતાવની દી હૈ કી યદિ શાસન ને સીધી હી ઇસે અનિવાર્યતા સમાસ નહીં કી તો આદેલાન કો

ઔર તું કિયા જાએના। ઉછોનેને માંગ રહ્યી કી પરંપરાગત ઉપસ્થિતી પ્રાણીની કો ફિર સે લાગુ કિયા જાએ, તાકિ કર્મચારીયોંની નેટવર્ક યા તકનીકી સમયાં કા ખામીયાજ ન ભૂગતાન પડે। ફિલહાલ પ્રશાસન ને ઇસ પર કોઈ આધિકારિક બયાન જારી નહીં કિયા હૈ, લોકિન કર્મચારી સંઠાંનો કા આક્રોશ લાગાતું બઢ રહ્યું હૈ। અને વાલે દિનોને યા વિરોધ ઔર વ્યાપક રૂપ લે સકતા હૈ।



શિક્ષકોને સમસ્યાઓનો લેકર શિક્ષા અધિકારી કો સૌંપા જ્ઞાપન

તેંદુંધેડા। બ્લોક કે સમસ્ત શિક્ષકોની કી દ્વારા બુધવાર કે વિકાસસંદૂંદ શિક્ષા અધિકારી કી જ્ઞાપન સૌંપા ગયા, જિસમાં બતાયા ગયા કી વર્તમાન મંનું અનેલાન ઈ-અટેક્સ પ્રાણીની કી દર્જ કરાના કારણ અનેક સમસ્યાઓની કી દર્જ કરાયા હૈ। વર્તમાન ઈ-અટેક્સ એપ મંનું લગતાર તકનીકી ખામીયાં (જેસે રાશિ કટાન, ફૉડ કોલ, સિસ્ટમ ટ્રુટોન્ઝ) આ રહી

નામદાર, નારાયણ સિંહ રાજપૂત, ટાકુરડાસ અવચ્ચી, જિતદેવ બાંગાર, દૌલત સિંહ ટાકુર, રાજેશ રેણા, પુરુષોત્તમ સરેણા, યુરેણ જૈન, યોગેંદ્ર જૈન, શેંકદ ખરે, કાંદીરામ આહરવાર, મનમાર અહરવાર, ઇંદ્ર કુમાર પંડ્યામ, ગુડ્ધા પાલ, કુદુન ઉપાધ્યાય, મહેંદ્ર જૈન, ગણેશ પાટક સહિત રેક્લો શિક્ષક ઉપસ્થિત રહે।

તેંદુએ કી દસ્તક સે ગ્રામીણોને મંનું, બછડે પર હુમલા કિયા

કટની, દોપહર મેટ્રો

રિયાશી ઇલાકોને મંનું ખુબાન વન્ય જીવ તેંદુએ કી આત્મક દિનોને દિન બદાની હી જા રહ્યા હૈ, અબ કટની જિલે મંનું દેખેને કો મિલા હૈ। યાં કટની જિલે કે બરહી નાર સે લાગે ખુજું ગાંધી મંનું તેંદુએ કી દસ્તક સે ગ્રામીણોને મંનું કર્યા હૈ। રાત કારીબ 11 બજે એક તેંદુએ ને અભાસ પાઈનાની કો ખેતે મંનું બંધે બછડે પર હુમલા કર દિયા। ગ્રામીણોને કો શેર મંનું પર હુંચ ગઈ હૈ। રેંજર ગોવિંદ નારાયણ શુક્રા ને બતાયા કી તેંદુએ ખાંદોના દુસ્તાન પર હુંચ ગઈ હૈ। ઇસ ઘણાને કે બાદ સે ગ્રામીણોને મંનું કર્યા હૈ। કોઈ ખેતે મંનું નહીં કર્યા હૈ। એસે કુછ જિલોને પર હુંચ ગઈ હૈ। યાં સે 11 મકાન હાટાએ જા રહે હૈનું। ઇસ કાર્બાવાઈ કો દેખેને હુંચ મંનું પર હુંચ ગઈ હૈ। યાં તકનીકી ખામીયાં (જેસે રાશિ કટાન, ફૉડ કોલ, સિસ્ટમ ટ્રુટોન્ઝ) આ રહી

ઉજ્જૈન કે બેગમબાગ મંનું પહુંચી જેસીબી ઔર પોકલેન દેખ મચા છાંકંપ, પુલિસ બલ તૈનાત

લીજ કી શર્તોને ઉલ્લંઘન મામલે મંનું સંયુક્ત કાર્બાવાઈ

ઉજ્જૈન, દોપહર મેટ્રો

ઉજ્જૈન મંનું લીજ કી શર્તોને ઉલ્લંઘન મામલે મંનું અને વિકાસ પ્રાથિકરણ ઔર નાગ નિગમ કી સંયુક્ત ટીમ ને ગુરુવાર સુશુદ્ધ બેગમબાગ મંનું જેસે ખોલ્લો પોકલેન મંનું લેકર પહુંચ ગઈ હૈ। યાં સે 11 મકાન હાટાએ જા રહે હૈનું। ઇસ કાર્બાવાઈ કો દેખેને હુંચ મંનું પર હુંચ ગઈ હૈ। યાં ને એસે 11 મકાનોનો કો આજ તોડા જા રહી હૈ। ટીમ ને મકાનોનો કો તોડાના શુદ્ધ કર દિયા હૈ। યાં મંનું અંગરા સેરેન્ટોર્સ અને એસ્પેશન કર્યા હૈ। યાં મંનું પુલિસ બલ તૈનાત કર્યા હૈ। ઇસથી પછીને હુંચ મંનું પર હુંચ ગઈ હૈ।



લિયા ગયા હૈ। ઇન્ના હી નહીં જીમન બેચ ઔર ખરીદ ભી લી ગઈ હૈ। એસે 11 મકાનોનો કો આજ તોડા જા રહી હૈ। ટીમ ને મકાનોનો કો તોડાના શુદ્ધ કર દિયા હૈ। યાં મંનું અંગરા સેરેન્ટોર્સ અને એસ્પેશન કો મંનું દર્દી હોયું હૈ। ઇસથી પછીને હુંચ મંનું પર હુંચ ગઈ હૈ।

ટ્રક ને કાર કો મારી ટકકર, પતિ-પત્ની, બહનોઈ ઔર ભાંજે કી મૌત

ગોલાકોટ તીર્થ જા રહેથાના દોપહર મેટ્રો

ગોલાકોટ તીર્થ સ્થળ જા રહે થાં। પુલિસ સે મિલોની કો ખાંસી લોકોની કી દર્જ કરેલી જાન પરિવાર કે સંદર્ભ નિર્ણય ના કોઈ પણ કાર્યક્રમ

